

दुनिया आपके
उदाहरण से
बदलेगी आपकी राय
से नहीं।

- अज्ञात

विचार-प्रवाह

देहरादून रविवार 29 दिसंबर 2019

पेज थ्री

www.page3news.in

ढांचे में बुनियादी बदलाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे में रिफॉर्म के लिए कई अहम फैसले किए। रेलवे की आठ विभिन्न सेवाओं को मिलाकर सरकार ने 'इंडियन रेलवे' में नामक एक नई सेवा के गठन का फैसला किया है।

आलोक प्रसाद

सरकार रेलवे के प्रबंधन ढांचे में बुनियादी बदलाव करने जा रही है। उसका दावा है कि इससे भारतीय रेल के विभिन्न विभागों के बीच वर्चस्व की लड़ाई व गुटबाजी खत्म होगी और कामकाज में सरलता व पारदर्शिता आएगी। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि इससे चीजें और भी उलझेंगी।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे में रिफॉर्म के लिए कई अहम फैसले किए। रेलवे की आठ विभिन्न सेवाओं को मिलाकर सरकार ने 'इंडियन रेलवे' में नामक एक नई सेवा के गठन का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड में अब चेयरमैन के अलावा सिफ़ चार कार्यकारी मैंबर होंगे और ये पांचों कुल पांच विभागों ऑपरेशन, विजेन्स डिवेलपमेंट, हाउसन रिसोर्सेज, इन्फ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस की जिम्मा संभालेंगे। इनके अलावा कुछ स्वतंत्र अनुभवी

विशेषज्ञ भी बोर्ड से जुड़ेंगे, जिसके लिए उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र और प्रबंधन का 30 वर्ष का अनुभव जरूरी होगा। बोर्ड के चेयरमैन का अब चेयरमैन—सह—सीईओ के नाम से जाना जाएगा। सरकार का कहना है कि काडरों की आपसी प्रतिव्वादिता के कारण फैसले लेने में दिक्कत होती थी। कई महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट्स इसी कारण लटक गए। जैसे इलेक्ट्रिकल और मकैनिकल काडर के बीच खिचतान की वजह से महत्वाकांक्षी ट्रेन 18 प्रॉजेक्ट पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बोर्ड में स्थायी सदस्यों को लेने से पैदा होने वाली जटिलता पर पहले ही ठीक से सोच लेना चाहिए। बाहरी मैंबरों का हस्तक्षेप बोर्ड के सीईओ और कार्यकारी सदस्यों को खटक सकता है। वैसे भी रेलवे के कामकाज में विशेषज्ञों को शामिल करने का अनुभव

मौजूदा अफसरों के लिए नई सेवा में खुद को ढालना आसान नहीं होगा।

इससे उनकी वरीयता प्रभावित हो सकती है, जिसका उनके मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा। फिर नई भर्तियों के लिए भी नया ढांचा खड़ा करेगा।

आधी ऊर्जा इन कार्यों पर खर्च होने से रेलवे के कामकाज पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बोर्ड में स्थायी सदस्यों को लेने से पैदा होने वाली जटिलता पर अपरिवेषित हो जाएगी। बाहरी मैंबरों का हस्तक्षेप बोर्ड के सीईओ और कार्यकारी सदस्यों को खटक सकता है। जब उन्हें अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव भी किया है।

अच्छा नहीं है। इस दिशा में कायाकल्प

परिषद का प्रयोग असफल ही रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार रेलवे के केंद्रीकरण और कॉर्पोरेटीकरण में जुटी है। बोर्ड में स्थायी सदस्य कम रखने और चेयरमैन को सीईओ बनाने के पीछे मंशा यही है कि सरकार इस दिशा में बेझिक्क आगे बढ़ सके। सरकार चेयरमैन की भूमिका बढ़ा रही है, पर अभी तक उसका कार्यकाल तय नहीं किया गया है। इसीलिए वह ढांचे से कोई काम नहीं कर पाता। रेलवे यूनियन नेताओं का कहना है कि ये सुधार निजीकरण को आसान बनाने के लिए हैं। बहराहाल, एक बात तो है कि सरकार रेलवे में सुधार के लिए चिंतित है। उम्मीद करें कि इतने बड़े फैसले ठीक से सोच—विचार करके ही लिए जा रहे होंगे।

ऊर्जा बुद्धिमत्ता है

आसू ध्यान के अभ्यास का उद्देश्य स्वस्थ होना और परिवर्तन लाना है। यह हमारी पूर्ण होने में और हमें हमारे आसपास की वास्तविकता जानने के लिए अपने अंदर और

आसपास देखने में मदद करता है।

ध्यान में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा बुद्धिमत्ता है। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखने और उन के दिल में गहराई से उतरने के लिए। जब बुद्धि मौजूद होती है, ध्यान मौजूद होता है। बुद्धि ध्यान लगाने की वस्तु के असली सार को समझने में हमारी मदद करती है। चाहे ये एक धारणा हो, एक भावना हो, एक कार्यवाई हो, एक प्रतिक्रिया हो, एक व्यक्ति या वस्तु की उपरिथिति हो।

गहराई से देख कर, ध्यान का अभ्यास करने वाले अंतर्दृष्टि, प्रज्ञा, या ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस जानकारी में, हमारे दुख और बंधन से हमें मुक्त करने की शक्ति है।

संपादकीय

जनता ही जनादन

लोकतंत्र में जनता और उसके जनादेश का नजरिया कभी स्थाई नहीं होता। सरकारें अगर जनता के विश्वास पर खड़ी नहीं उत्तरतीं तो उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सरकारों को आम लोगों के नजरिये को गहराई से समझना चाहिए। लोकतंत्र में जनता ही जनादन है। लेकिन सत्ता की अकड़ डुबोती है। ज्ञारखंड का जनादेश कम से कम यहीं संदेश देता है। सरकारों को इस भूल से निकलना चाहिए। केंद्र और राज्य की कमान एक ओर से नहीं खींची जा सकती। बदलते राजनीतिक समीकरण में बीजेपी और कांग्रेस जैसे केंद्रीय दलों के लिए यह बड़ी चुनौती है। राज्यों में वह बगैर कंधे के नहीं सफल हो सकती है। ज्ञारखंड में बीजेपी की परायज की वजह भी यही है। राज्य की जनता ने केंद्रीय मुद्दों को किनारे रखा आदिवासी समस्याओं को तरजीह दी। बीजेपी जहां नागरिकता बिल और धारा-370 में अटकी रही वहीं ज्ञारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा चेहरा हेमंत सोरेन ने आदिवासी पीड़ा हो अच्छी तरह समझा और उसी मसलों पर चोट किया जिसकी वजह से बीजेपी बैकफूट पर चली गई। आजसू जैसे विश्वसनीय सियासी दोस्त को भी बीजेपी ने किनारे रखा। ज्ञारखंड से निकला जनादेश का संदेश बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व के लिए बड़ी सीख है। बीजेपी की राजनीतिक साख और जनविश्वास का सूचकांक गिर रहा है। एक साल में बीजेपी ने पांच राज्यों को गंवा दिया। मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद ज्ञारखंड में भी बीजेपी का सफाया हो गया। 2019 में बीजेपी केंद्र में बड़े बहुमत से भले सत्ता में आई, लेकिन राज्यों में खिसकता जनाधार उसकी पकड़ कमजोर बना रहा है। हालांकि इस दौरान उसने कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में सरकार बनाई है। सात माह में 18 फीसदी वोट घटे हैं यह बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व की नींद उड़ाने वाला है।

लगातार दो लोकसभा चुनावों में बहुत कमजोर प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस ने अपना हौसला नहीं छोया। अभी देखने में आ रहा है कि उसने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव भी किया है।

कांग्रेस ने हौसला नहीं छोया

राधा शर्मा

ज्ञारखंड के चुनावी नतीजों ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को गहरा झटका दिया है। ज्ञारखंड में हार के साथ ही बीजेपी ने अपने शासन वाले जो पांच राज्य गंवाए हैं, उन सभी में कांग्रेस या तो सीधे या फिर एक भागीदार के रूप में सत्ता में आ गई है। वर्ष 2014 के बाद से ही बीजेपी लोगों को यह समझाने में जुटी हुई है कि एक सियासी ताकत के रूप में कांग्रेस तेजी से सिकुड़ रही है और जल्द ही यह अतीत का हिस्सा बन जाएगी। आश्वर्य की बात यह कि जब पिछले दिनों सीएए—एनआरसी को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शनों को सिलसिला शुरू हुआ तो बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा कि यह कांग्रेस ही है जो लोगों को भड़का रही है। यानी अनजाने में उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस की उपरिथित देश भर में है और उसका असर जनता के एक बड़े तबके पर है।

यह बात उत्तरी न सही पर काफी हद तक सच है। लगातार दो लोकसभा चुनावों में बहुत कमजोर प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस ने अपना हौसला नहीं छोया। अभी देखने में आ रहा है कि उसने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव भी किया है। खुद को स्वाभाविक शासक समझने की



महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने से पहले उसने कॉमन मिनिम म प्रोग्राम पर जोर दिया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सावरकर पर अपने विचार खुलकर व्यक्त किए और शिवसेना के विरोध के बावजूद नरमी का कोई संकेत नहीं दिया। दरअसल कांग्रेस के सामने अभी दोहरी चुनौती है। बीजेपी के आक्रमक हिंदुत्व से आशकित लोग कांग्रेस से वैचारिक हस्तक्षेप की उम्मीद लगाए हुए हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई का नेतृत्व करने की अपेक्षा उसके सिवाय और किसी से की भी नहीं जा सकती। लेकिन कांग्रेस का ढांचा किसी वैचारिक लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है। उसकी दूसरी लाइन के नेताओं के लिए सत्ता में बने रहना और अपनी खोई जमीन हासिल करना ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है।

सच कहें तो कांग्रेस के लिए दोनों दायित्व बराबर के लिए हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस की वैचारिक जमीन मजबूत करने की कोशिश की जिससे पार्टी में असंतोष फैला और उसकी सियासी भूमिका प्रभावित हुई। उनके उलट कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का जार पार्टी ढांचे को साथ रखने पर है। कांग्रेस का भविष्य इन दोनों पहलुओं के संतुलन से ही तय होना ह